कोटद्वार, मंगलवार
2 जुलाई 2024
वर्ष: 46
अंक: 69 पृष्ठ: 4
मूल्य: 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

उत्तराखंड के इस थाने में नए कानूनों के तहत दर्ज हुई पहली एफआईआर

देहरादून।उत्तराखंड में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर सोमवार को हरिद्वार जिले के ज्वालापुर थाने में दर्ज की गई। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309 (4) (डकैती) के तहत दर्ज की गई। यदि आईपीसी अभी भी अस्तित्व में होती, तो यह एफआईआर धारा–392 के तहत दर्ज की जाती। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रात करीब 1:45 बजे गंगा नदी के किनारे रविदास घाट पर बैठा था, इसी दौरान दो अज्ञात लोग आए और चाकू की नोंक पर उसका मोबाइल फोन और 1400 रुपये नकद लूट लिए। बदमाशों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने उसे नदी की ओर धकेल दिया और भाग निकले। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने शिकायत मिलने के आधे घंटे के भीतर ही पहली एफआईआर दर्ज कर ली। जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि हर नई चीज के क्रियान्वयन के साथ चुनौतियां भी आती हैं। हमें शिकायतकर्ता की ओर से सुबह करीब 10:30 बजे शिकायत मिली थी। इसके आधे घंटे के भीतर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि इस दौरान पुलिस को नए कानूनों के प्रावधानों से गुजरना पड़ा। इसके लिए डिजिटल डिवाइस पर रिकॉर्ड और सबूत रखे गए। जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि जल्द ही हमें नए कानूनों के तहत काम करने का अभ्यास हो जाएगा।

नए आपराधिक कानूनों पर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में लगभग 25 हजार पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। इन आपराधिक कानूनों के लागू होने से देश में कानून व्यवस्था की स्थित में सुधार होगा।

मालदेवता सिल्ला सेरकी मार्ग पर मलबा आने से दस घंटे आवाजाही ठप

देहरादून। मालदेवता सिल्ला सेरकी मार्ग पर देर रात करीब बारह बजे बारिश के बाद मलबा और बोल्डर आने से बाधित रहा। इससे विभिन्न गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह करीब दस बजे वाहनों का संचालन शुरू हो पाया।स्थानीय निवासी संतोष काला ने बताया कि बारिश के बाद मालदेवता सिल्ला सेरकी मार्ग पर रविवार देर रात जगह– जगह मलबा और बोल्डर का ढेर लग गया। उन्होंने बताया कि सुबह गांव से आवाजाही के दौरान ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटवाने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी इस पूरे क्षेत्र में बरसात के दौरान काफी नुकसान हुआ। लोगों ने मांग की है कि बारिश के दौरान राहत व बचाव कार्य के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

राज्य कर कर्मियों का कार्यबहिष्कार शुरू, दो घंटे ठप रहे कार्यालय

देहरादून। राज्य कर अधिकारी संवर्ग के 243 पद समाप्त करने के विरोध में राज्य कर कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोमवार को प्रदेश भर के अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यबहिष्कार किया। कर्मियों ने यह आंदोलन पद पुनर्जीवित होते तक जारी रखने का ऐलान किया है। रिंग रोड स्थित कर मुख्यालय में कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी सुबह 10 बजे ही कामकाज छोड़कर अपने कार्यालयों से बाहर निकल आए। इस मौके पर राज्य कर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी न कहा कि सरकार ने 28 जून को विभागीय अधिकारियों के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। इसमें राज्य कर अधिकारी संवर्ग के पदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। न ही इस पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है। मोर्चा के महासचिव अरविन्द जोशी, मिनिस्ट्रीयल संघ के संरक्षक भरत सिंह राणा, सलाहकार मनमोहन सिंह नेगी ने कहा कि इससे पहले भी दो बार शासन ने अधिकारियों का ढांचा पुनर्गठित करते हुए अधिकारियों के पदों में बढ़ोत्तरी की है। लेकिन कर्मचारियों के ढांचे में एक बार भी कोई वृद्धि नहीं की गई।

नए कानून न्याय की अवधारणा को करेंगे मजबूत : मुख्यमंत्री

देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया औपचारिक शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का राज्य में औपचारिक शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण देश में आज से तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023" लागू हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तीन नए कानूनों पर आधारित कड एप्लीकेशन का शुभारंभ एवं विवेचक पुलिसकर्मियों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून के लागू होने पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। ये तीनों कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे। ये कानून गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए कानून आजादी के अमृत महोत्सव के बाद के कालखंड में देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगा।

राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान

पीएम मोदी ने कहा—पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय

शाह बोले– माफी मांगें नेता प्रतिपक्ष

नईदिल्ली, संसद में धनवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर संसद में घमासान मचा हुआ है. राहुल गांधी के पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं होने वाले बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. पीएम मोदी ने अपनी सीट पर खड़े होकर कहा कि हिंदू को हिंसक कहना गलत है. पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है. इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अभय की बात करने का कोई हक नहीं है. इन्होंने इमरजेंसी के दौरान पूरे देश को भयभीत करा. इनको सदन में माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाकर बंद कर दिया था. इस धर्म पर करोड़ों लोग गर्व से हिंदू कहते हैं. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय लें.राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेज आवाज में बोलने और शोर शराबा कर के इतने बड़े मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता है. विपक्ष के नेता ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं. इस देश में करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, इस सदन में और वो भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा गलत है. इसी के साथ अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की.

राहुल गांधी के भाषण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चेयर से खड़े होकर कहा कि मुझे लोकतंत्र ने सिखाया है कि विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मैंने अयोध्या पर बोला है, अनुराग ठाकुरजी अयोध्या की बात कर रहे थे, उस पर की है.

दो दिन में 28,534 यात्रियों ने किये बाबा बर्फानी के दर्शन

अमरनाथ यात्रा

जम्मू,। जम्मू से सोमवार को 6,461 यात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिन में 29 और 30 जून को 28 हजार से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिन में 28,534 श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए। एक अधिकारी ने कहा, आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 6,461 यात्रियों का एक और जत्था दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 2,321 यात्री 118 वाहनों के काफिले में सुबह 3.15 बजे उत्तरी कश्मीर के बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए।

वहीं, 147 वाहनों के एक अन्य सुरक्षा काफिले में 4,140 यात्री सुबह 4.10 बजे दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर के लिए रवाना हुए। इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को रक्षा बंधन पर समाप्त होगी। यात्री 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम–गुफा तीर्थ मार्ग से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल–गुफा तीर्थ मार्ग से यात्रा करते हैं। पहलगाम मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने पर दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस आधार शिविर लौट सकते हैं। समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊंचाई स्थित गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती–बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है। इस वर्ष लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग पर, दोनों यात्रा मार्गों पर, दोनों आधार शिविरों पर और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारू और निर्बाध हो सके। दोनों मार्गों पर और पारगमन शिविरों और गुफा मंदिर में 124 से अधिक लंगर लगाए गए हैं। इस वर्ष की यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक सेवादार (स्वयंसेवक) यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।

पुणे में पिकनिक मनाने गया था परिवार, झरने में डूबने से 4 बच्चों समेत पांच की मौत

पुणे ,लोनावाला हिल स्टेशन के निकट एक झरने में एक महिला और चार बच्चों सहित पांच लोग बह गए और डूब गए। लोनावाला पुलिस स्टेशन के प्रभारी मयूर अग्नवे ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर करीब दो बजे हुई। जब बच्चे व कुछ अन्य लोग भूशी बांध के पास पहाड़ी जंगलों में बह रहे झरने का आनंद लेने गए थे।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना की शिकार महिला की उम्र करीब 40 वर्ष और बच्चों की उम्र 4 से 8 वर्ष के बीच है। ये सभी पुणे के सैय्यद नगर के निवासी थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे झरने के तल पर काई लगे पत्थरों पर फिसलकर पानी के वेग में बह गए होंगे और डूब गए होंगे। अग्नवे ने बताया कि स्थानीय लोग और पुलिस की बचाव टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।ताजा जानकारी के अनुसार, इस घटना में 40 वर्षीय महिला और एक 13 वर्षीय और एक 8 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4–9 वर्ष के तीन बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। स्थानीय एसपी ने एक बयान में बताया कि ऐसा लगता है कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं और भुशी बांध से लगभग दो किलोमीटर दूर झरने में फिसल गए, जहां वे डूब गए।

पहाड़ी फिल्म फूली को टैक्स फ्री किया जाय : महाराज

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर पदमा सिद्धि फिल्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं अविनाश ध्यानी द्वारा निर्देशित पहाड़ी फिल्म ह्वफूलीह्व को टैक्स फ्री करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी फिल्म ह्वफूलीह्व देहरादून सहित उत्तराखंड के विभिन्न सिनेमाघर में दिखाई गई, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया है इसलिए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए।

प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पहाड़ी फिल्म ह्वफूलीह्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान जैसे विषयों पर आधारित है। यह फिल्म बेहद प्रेरणादायक है। इसमें पहाड़ के गांवों में रह रहे बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। फूली फिल्म को स्कूली बच्चों को अवश्य दिखाना चाहिए, ताकि वह इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और देश की सेवा करें। मुख्यमंत्री धामी ने महाराज के अनुरोध को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस को देखकर इसे टैक्स फ्री करवाने के लिए प्रयास किए जाने की बात कही थी।

लागू हुए तीन नए कानून, तीन साल के भीतर मिलेगा न्याय

नई दिल्ली, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से देश में लागू हो गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। तीनों कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए थे। नए कानून देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट की जगह आए हैं। नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग का भी है। इसके अलावा 41 विभिन्न अपराधों में सजा बढ़ाई गई है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है, 25 अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है।

इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी। कुल 24 धाराओं में बदलाव किया है। नई धाराएं और उपाधाराए जोड़ी गई हैं।

सरकार का मानना है कि नए कानून लागू होने से न्याय जल्दी मिलेगा और तय समय के अंदर चार्जशीट फाइल हो सकेगी। साक्ष्य जुटाने के लिए 900 फॉरेंसिक वैन देशभर के 850 पुलिस थानों के साथ जोड़ी जा रही हैं। गरीबों के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में नौ नए सेक्शन और 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। इसके अलावा 44 नई व्याख्याएं और स्पष्टीकरण जोड़े हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक संसद में रखे थे, जिन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया। पिछले साल 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दी थी। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि विधेयक का उद्देश्य दंड देना नहीं है, इसका उद्देश्य न्याय देना है। उन्होंने कहा था कि इन विधेयकों की आत्मा भारतीय है। व्यास, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वात्स्यायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि अनेक लोगों ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उसको इसमें उतारा गया है। सरकार का मानना है कि यह कानून स्वराज की और बड़ा कदम है। गृह मंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। ये कानून लागू होने से तारीख पर तारीख का जमाना चला जाएगा। तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रतिस्थापित होगी।

सभी सांसद संविधान में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही लें संसद सदस्यता की शपथः लोकसभा स्पीकर

नई दिल्ली,संसद सदस्यता की शपथ लेते समय कई नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा नारेबाजी और अलग–अलग शब्दों का प्रयोग करने के कारण हाल के दिनों में कई बार विवाद खड़ा हो गया था। इन विवादों को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में यह व्यवस्था दे दी है कि सभी सांसद संविधान में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही संसद सदस्यता की शपथ लें। उन्होंने भविष्य में शपथ के दौरान सांसदों द्वारा कोई अतिरिक्त शब्दों या नारों का उल्लेख नहीं करने की हिदायत देते हुए इस संबंध में सभी दलों के सांसदों को शामिल कर, एक संसदीय समिति का भी गठन करने की जानकारी दी। ओम बिरला ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सदस्यों के शपथ के लिए संविधान में प्रारूप दिया गया है और उसी प्रारूप के अनुसार ही शपथ ग्रहण करना सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है।

भारत ने विकसित किया दुनियां का सबसे खतरनाक विस्फोटक

चंद सेकंड में मचा देगा तबाही

नईदिल्ली, भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नई उपब्धियां हासिल कर रहा है. इसके साथ ही भारत रक्षा उत्पादन में भी पड़ोसी देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है. इस बीच भारत ने एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ तैयार किया है जो ट्राइनाइट्रोटॉल्विन से दोगुना ज्यादा घातक है. जिसे सेबेक्स 2 नाम दिया गया है. जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर गैर–परमाणु विस्फोटकों में से एक माना जा रहा है.

इस विस्फोटक के इस्तेमाल से बमों, आर्टिलरी शेल्स और वारहेड्स की क्षमता में कई गुना बढ़ा देगा. यही नहीं इस नए विस्फोटक का वजन भी काफी कम है. सेबेक्स–2 के फॉर्म्युलेशन को भारतीय नौसेना ने सोमवार को टेस्टिंग के बाद सर्टिफाई भी कर दिया है.

इस विस्फोटक की भारतीय नौसेना के डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत टेस्टिंग की गई है. इस विस्फोटक के इस्तेमाल से वर्तमान हथियारों की क्षमता में कई गुना की बढ़ोतरी होगी. यही नहीं भारत द्वारा विकसित कि गए इस विस्फोट को दुनियाभर की सेनाएं इस्तेमाल करने के लिए आगे आएंगी. बता दें कि इस इस विस्फोटक को मेक इन इंडिया के तहत, इकॉनोमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने विकसित किया है.

ग्लोबल इंडियाएआई समिट एआई के विकास और पहुंच को बढ़ाएगा : केंद्र

नई दिल्ली,केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि इस हफ्ते होने वाली ग्लोबल इंडियाएआई समिट का उद्देश्य साझेदारी, ज्ञान के आदान–प्रदान, नैतिकता के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजीज का समावेशी विकास करना है। आईटी मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया कि ये समिट 3 से 4 जुलाई के बीच देश की राजधानी दिल्ली में होगा। इसमें सदस्य देशों के एक्सपर्ट भाग लेंगे और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) का नेतृत्व भारत करेगा। ये प्लेटफॉर्म विज्ञान, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और शैक्षणिक विभागों के एक्सपर्ट्स को एक मंच प्रदान करेगा। जहां वे एआई से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर बातचीत करेंगे।

आईटी मंत्रालय ने आगे कहा कि यह इवेंट सरकार की एआई को लेकर प्रतिबद्धता को दिखाता है। सरकार इसके जरिए सभी एआई पक्षकारों में साझेदारी और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीपीएआई के नई दिल्ली डिक्लेरेशन को 28 देशों की ओर से अपनाया गया। इस डिक्लेरेशन में फोकस नए अवसरों की पहचान करने और एआई के विकास, उपयोग और लागू होने से आने वाले जोखिमों को कम करना था। जीपीएआई ने यह सुनिश्चित किया है कि एआई स्पष्टता और जवाबदेही के साथ करोड़ों लोगों के लिए एक तेज प्रवर्तक की भूमिका निभाए।

सरकार के मुताबिक, इंडियाएआई मिशन का उद्देश्य एक कॉम्प्रीहेन्सिव इकोसिस्टम तैयार करना है, जो कि कंप्यूटर तक पहुंच में लोकतंत्रीकरण, डेटा की गुणवत्ता को सुधार कर, स्वयं की एआई क्षमताएं विकसित कर, शीर्ष एआई टैलेंट, इंडस्ट्रीज के बीच साझेदारी, स्टार्टअप को रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराने, समाज में बदलाव लाने वाले एआई प्रोजेक्ट के जरिए एआई इनोवेशन को बढ़ाना है। आईटी मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस समिट का फोकस भारत के एआई इकोसिस्टम का जिम्मेदार और समावेशी विकास करना है।

दिल्ली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना

नईदिल्ली,दिल्ली में बारिश का क्रम शुरू हो गया है। यहां अलग–अलग इलाकों में अगले 7 दिन तक लगातार रुक–रुककर बारिश की संभावना जताई गई है।इस बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में 2–3 जून को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।बारिश के बाद से राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है।

दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में हुई 228.1 मिलीमीटर बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बारिश 27 जून को सुबह 8:30 बजे से 28 जून सुबह 8:30 बजे के बीच दर्ज की गई थी।

अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी

दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नईदिल्ली,दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। साथ ही 26 जून के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था।मामले पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 जून को मुख्यमंत्री को 3 के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। उन्होंने कहा था कि इस स्तर पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता।इसके 3 दिन बाद 29 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि सीबीआई ने आगे की रिमांड नहीं मांगी थी।केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत केजरीवाल पहले से जेल में बंद हैं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, जिस पर है कोर्ट ने रोक लगा दी। बीच में उन्हें 21 दिन की जमानत मिली थी, लेकिन 26 जून को मंगलवार रात सीबीआई ने उनसे जेल में पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

संपादकीय

बयान पर घमासान

18वी लोकसभा की कार्रवाई में अभी तक ऐसा एक भी दिन नजर नहीं आया है जहां बिना गतिरोध के जनहित के मामलों को लेकर काम हो रहा हो। पूरा सदन आप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच झूल रहा है तो इधर राहुल गांधी के सदन में दिए गए एक बवाल ने तो बवंडर ही पैदा कर दिया है। पूरा सदन अब राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रामक मुद्रा में है तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों के वार से अपना पक्ष रखने की कोशिश भी शुरू हो गई है। बयान का असर सदन के बाहर सड़कों पर भी नजर आने लगा है लिहाजा निश्चित है कि आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर राजनीति पूरे तूफान पर नजर आएगी। सदन में सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है तो उधर पूरा विभाग राहुल गांधी के साथ खड़े होकर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि सत्तारूढ़ दल के नेता हिंदू नहीं हैं क्योंकि वे हिंसा और बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। बयान पर बवाल होना निश्चित था और वही सब हुआ भी। सदन में जनहित को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों से किनारा करते हुए पूरा ध्यान अब बयान को लेकर शोरगुल में केंद्रित हो चुका है। वही विपक्षी नेताओं का कहना कि राहुल ने हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि भाजपा नेताओं के बारे में टिप्पणी की थी, लेकिन राजनीति में तिल का ताड़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और यहां भी भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर ही एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो सीधा हिंदुत्व के इर्द-गिर्द घूमता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए उनका यह दिया गया बयान आने वाले दिनों के लिए कुछ मुसीबत तो पैदा कर ही सकता है साथ ही चुनावों के दौरान जो एक छवि उन्होंने अपनी बनाई थी उस पर भी सत्ता पक्ष हमला करने से पीछे नहीं हटेगा।

भाजपा ने भले ही इस पूरे मुद्दे को हिंदुओं से जोड़कर पेश किया है लेकिन विपक्ष भी चीख चीख कर यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सदन में राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में टिप्पणी की थी। विपक्ष के लिए भी अब इस बयान को लेकर पैदा हुई स्थिति को नियंत्रित करने में कुछ परेशानी तो हो ही रही है तो साथ ही वही अब पूरे सदन की निगाह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी जहां वह इस बयान पर अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी अपने बयान पर कहीं ना कहीं अब घूरते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं और यदि वे अब अपना लाख पक्ष भी रखें तो भी वह इस मुसीबत से अब इतनी आसानी से छुटने वाले नहीं है और ना ही भाजपा इतनी आसानी से इस मुद्दे को जाने देगी।

रोजगार की जरूरत

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) के द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2024) में बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.5 प्रतिशत थी। शहरी बेरोजगारी पिछली चार तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 15 साल से अधिक उम्र में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही के 6.8 प्रतिशत के बाद सर्वाधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी स्तर बढ़ा है और यह बीती तिमाही के 16.5 प्रतिशत से बढकर चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शहरी रोजगार के बाजार में गिरावट का पता चलता है। अब नई सरकार के द्वारा देश में असंगठित सेक्टर लघु एवं मध्यम उद्योगों और गिग वर्कर्स की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना होगा। इन सेक्टरों में करोड़ों लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। जून 2022 में प्रस्तुत नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस समय गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

यकीनन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नई एनडीए गठबंधन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती नौकरियों और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने की है।

हाल ही में दुनिया में आर्थिक और रोजगार से संबंधित शोध अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सिस एसए के द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिस तेजी से युवा रोजगार के लिए तैयार होकर श्रम शक्ति (वर्क फोर्स) में शामिल हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को 2030 तक प्रति वर्ष 1.65 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसमें से करीब 1.04 करोड़ नौकरियां संगठित सेक्टर में पैदा करनी होगी। जबकि पिछले दशक में सालाना कुल 1.24 करोड़ नौकरियां ही पैदा हो सकी थीं।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी को बरकरार रखने के लिए सर्विसेज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी सेक्टर्स को नई रफ्तार से बढ़ावा देना होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी में से 83 फीसद बेरोजगार युवा थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत की कुल श्रम शक्ति की भागीदारी दर मात्र 58 प्रतिशत है, जो भारत के एशियाई समकक्ष देशों की तुलना में बहुत कम है। निसंदेह नई गठबंधन सरकार को बेरोजगारी संबंधी चिंताजनक नए आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा। हाल ही पिछले दस वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में कम बहुत है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) के द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2024) में बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.5 प्रतिशत थी। शहरी बेरोजगारी पिछली चार तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 15 साल से अधिक उम्र में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही के 6.8 प्रतिशत के बाद सर्वाधिक है।

सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी स्तर बढ़ा है और यह बीती तिमाही के 16.5 प्रतिशत से बढकर चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शहरी रोजगार के बाजार में गिरावट का पता चलता है। अब नई सरकार के द्वारा देश में असंगठित सेक्टर लघु एवं मध्यम उद्योगों और गिग वर्कर्स की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना होगा। इन सेक्टरों में करोड़ों लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। जून 2022 में प्रस्तुत नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस समय गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी।

गिग वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या नौकरी जाने का खतरा और प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलना है। देश में रोजगार के मद्देनजर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। नैसकॉम के मुताबिक भारत के प्रौद्योगिकी कार्यबल में केवल 36 फीसद महिलाएं हैं।

विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों में महिलाओं की भागीदारी केवल 14 फीसद है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्र में महिलाओं का रोजगार कम है और भारत के बड़े अवसरों के लिए महिलाओं की कम भागीदारी चुनौतीपूर्ण है। निश्चित रूप से नई गठबंधन सरकार को देश की नई पीढ़ी को जॉब सीकर यानी नौकरी की चाह रखने वाले से ज्यादा नए दौर के जॉब गिवर यानी नौकरी देने वाले बनाने की तेज रणनीति के साथ भी आगे बढना होगा। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह नई पीढ़ी के द्वारा स्वरोजगार के मौके मुी में लिए जा रहे हैं।

उनकी रफ्तार बढ़ाई जानी होगी। हाल ही में शोध संस्थान स्कॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार मिले हैं। इस शोध अध्ययन में रोजगार व स्वरोजगार से संबंधित 12 केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएमईजीपी, पीएमए-जी, पीएलआई, पीएमएवाई-यू, और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 10 वर्षों में ंिआर्टफशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई स्किल्स से नई पीढ़ी को सुसज्जित करके उनके लिए रोजगार के मौके बढ़ाए हैं।

अब तीसरे कार्यकाल में देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों की (जीसीसी) स्थापनाओं की रफ्तार तेजी से बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ा जाना होगा। चूंकि कई विकसित और विकासशील देशों में तेजी से बूढ़ी होती आबादी के कारण उद्योग-कारोबार व सर्विस सेक्टर के विभिन्न कामों के लिए युवा हाथों की कमी हो गई तथा श्रम लागत बढने से ये देश कार्यबल संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत को इस मौके को भुनाते हुए तेजी से आगे बढना होगा। सरकार ने 2023 तक भारतीय श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई गठबंधन सरकार को ऐसे समझौतों को अब और बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढना होगा।

हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार के द्वारा उनके विकास के एजेंडे में शामिल अधिक रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। हम उम्मीद करें कि नई सरकार नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर पूर्णरूपेण ध्यान देते हुए लघु-मध्यम उद्योग और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की जरूरतों पर ध्यान देगी। साथ ही उम्मीद करें कि मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी 142 करोड़ से अधिक आबादी के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत में दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी को नए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल से सुसज्जित करके उनके चेहरों पर रोजगार की मुस्कुराहट देने के साथ देश की आर्थिक तस्वीर संवारने की संभावनाओं को साकार करने के लिए नई कारगर रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे।

नीट परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्नचिन्ह

अजय दीक्षित

देश के प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए) नीट परीक्षा आयोजित कराती है । (नेशनल एलिजिबिलिटी और इन्टरेंस टेस्ट) । इस वर्ष यह परीक्षा 7 मई को आयोजित हुई थी । परीक्षा के तत्काल बाद अनेक शहरों के छात्र-छात्राओं ने परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा की मांग की । शुरू में तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्नचिन्ह उठाने वालों को नकारा । पर जैसे-जैसे समय बीतता गया मालूम हुआ कि वास्तव में पेपर लीक हुआ था । पिछले दिन बिहार में पकड़े गये एक छात्र ने बतलाया कि परीक्षा से पहली रात उसे जिन प्रश्नों के उत्तर रटवाये गये थे, अगले दिन परीक्षा में हू-ब-हू वही प्रश्न आये । इस छात्र का कहना है कि उसके फूफा ने उसे एक रात पहले कोटा से पटना बुलाया और उसे बिचौलिए ने लगभग 25-30 लाख रुपये लिये । अब पुलिस को धरपकड़ में और भी छात्र-छात्राओं ने स्वीकारा कि उन्हें पर्चा पहले से मालूम था ।

असल में टेस्ट की पूरी प्रक्रिया क्या है ? किसी एक व्यक्ति से पहले पेपर बनवाया जाता है । अब कहा जा रहा है कि कई व्यक्ति पेपर बनाते हैं और फिर कोई एक वरिष्ठ इन सभी प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक नया पेपर तैयार करता है । इस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं कर सकता क्योंकि यह व्यक्ति बहुत वरिष्ठ और निष्ठावान होता है । अब प्रश्न पत्र टाइपकिया जाता है । कहा जाता है कि जो इसे टाइप करता है उसे परीक्षा होने तक एक प्रकार से कैद में रखा जाता है । या उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है । अब प्रश्न पत्र छपने के लिए किसी प्रिंटिंग प्रेस को भेजा जाता है । इस प्रेस का नाम भी कोई नहीं जान सकता ।

फिर पेपर कहां से लीक होता है? कहते हैं कि विभिन्न केन्द्रों में जो पेपर पहले भेज दिये जाते हैं, उन केन्द्रों से कहीं पेपर पहले खोल कर उसे लीक किया जाता है । यद्यपि यह भी असंभव लगता है क्यों कि परीक्षा के दिन पेपर पर पर्यवेक्षकों के सामने खोला जाता है और उनके हस्ताक्षर लिये जाते हैं । फिर हर सेंटर पर एन.टी.ए. का एक प्रतिनिधि भी रहता है ? शायद पेपर बनाने वाले या टाइप करने वाले या केन्द्र से पेपर लीक होता है । इसकी जो जांच हो रही है वह गोपनीय है । अतः विश्वास पूरक यह कहना कठिन है कि पेपर कहीं से लीक होता है । बिहार, गुजरात और अन्यत्र पकड़े गये लडके और लड़कियों ने स्वीकारा है कि उन्हें परीक्षा की पहली रात पेपर रटाया गया था, अब कहते हैं कि इस माफिया ग्रुप को कई करोड़ का लेन-देन प्रकट हुआ है । यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है । 20 जून को हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब आगामी तारीख 7 जुलाई को दी गई है । सुप्रीम कोर्ट ने चयन के लिए होने वाले साक्षात्कार पर रोक लगाने से अभी मना कर दिया है । पर जिस तरह से कुछ छात्रों ने पेपर लीक को स्वीकारा है तो क्या यह परीक्षा रद्द होगी । चलते-चलते खबर आई है कि यू.जी.सी. की नेट परीक्षा जो 16 जून को हुई थी उसे यू.जी.सी. ने निरस्त कर दिया है क्योंकि मंत्रालय को शक है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है ।

असल में इस परीक्षा के लिए विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है । जो ज्यादा अंक पाते हैं उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है । यहां फीस भी कम लगती है और पढ़ाई का स्तर भी काफी उंचा है । प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस कई गुना ज्यादा है और वहां की फैकल्टी भी उतनी अच्छी नहीं होती । इससे आगे चलकर उस विद्यार्थी को पी.जी. में प्रवेश भी नहीं मिल पाता । सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए को नौकरी भी अच्छे अस्पतालों में मिल जाती है । कुल प्रश्न बच्चों की मेहनत का है । कोटा या अन्यत्र इतना पैसा खर्च करके विद्यार्थी जो तैयारी करता है, वह व्यर्थ जाती है यदि परीक्षा रद्द कर दी जाती है । आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है । परन्तु कुल मिलाकर देश के युवाओं के साथ नीट परीक्षा में खिलवाड़ ही हुआ है? शायद भविष्य में सरकार और सख्त कदम उठाये क्यों कि मोदी जी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस रखते हैं ।

कारोबारी सुगमता का ध्यान

जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जीएसटी परिषद की इस पहली बैठक में रेलवे प्लेटफार्म टिकट, विश्राम कक्ष और प्रतीक्षालय सुविधाओं को जीएसटी मुक्त करने के महत्त्वपूर्ण फैसले के साथ ही सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12 फीसद की एक समान जीएसटी दर रखने का प्रस्ताव किया गया।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अनुपालन बोझ कम करने और करदाताओं को राहत देने की गरज से भी कई सिफारिश की गई। कोशिश है कि कारोबारी सुगमता के लिए व्यवसायों के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताएं कम की जाएं।

परिषद ने जीएसटी पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमीट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण के चरणबद्ध रोलआउट की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी रिमांड नोटिस पर ब्याज जुर्माना माफी की भी सिफारिश है।

यह धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें धोखाधड़ी, दमन या गलतबयानी शामिल नहीं हैं। जो करदाता 31 मार्च, 2025 तक नोटिस में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करते हैं, उन्हें इस छूट से लाभ होगा।

किसी चालान या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने संबंधी मंजूरी भी दी जा रही है। छोटे करदाताओं को भी इस रूप में राहत मिलने वाली है कि वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 20 अप्रैल से बढ़ा कर 30 जून की जाएगी।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसद की एक समान जीएसटी दर लागू होगी। दूध के सभी डिब्बों पर उनकी सामग्री (स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम) की परवाह किए बिना एक समान दर 12 फीसद की सिफारिश की गई है।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों की अरसे से मांग को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कार्टन बक्सों और नालीदार व गैर-नालीदार कागज या पेपरबोर्ड, दोनों से बने उत्पादों के लिए 12 फीसद जीएसटी का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के तहत लाने की सरकार की मंशा भी दोहराई। दरअसल, सिफारिशों में कारोबारी सुगमता को ध्यान में रखा गया है।

मानसून में फैशन के लिए नायलॉन और पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करती हैं विदिशा श्रीवास्तव

टीवी के पॉपुलर शो भाबीजी घर पर हैं में गोरी मेम का रोल अदा करने वाली विदिशा श्रीवास्तव ने मानसून फैशन ट्रेंड्स पर बात की। उन्होंने कहा कि वह मानसून में नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसी सिंथेटिक मटेरियल पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि वे मॉइश्चर-रेजिस्टेंस है और जल्दी सूख जाते हैं।

मानसून फैशन का मतलब है स्टाइलिश और कंफर्टेबल रहते हुए मौसम को एन्जॉय करना।विदिशा सिटकॉम भाबीजी घर पर हैं में अनीता भाभी का किरदार निभा रही हैं।उन्होंने कहा, बारिश के मौसम में, आपको स्टाइल से समझौता करने की जरूरत नहीं है। जब बारिश शुरू होती है, तो मैं नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़े पहनना पसंद करती हूं, जो मॉइश्चर को सोख लेते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं बारिश में हैवी कॉटन और वूलन कपड़ों को पहनने से बचती हूं, क्योंकि इन्हें सूखने में ज्यादा समय लगता हैं। मुझे ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए ब्राइट और बोल्ड प्रिंट वाले कपड़े पहनना पसंद है। प्लास्टिक जूलरी इस मौसम में फैशनेबल बने रहने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है।विदिशा ने कहा, मेरा पसंदीदा लुक एक स्टाइलिश वाटरप्रूफ जैकेट है, जिसे कलरफुल वाटरप्रूफ फुटवियर के साथ पेयर करना, और अपने आउटफिट में स्टाइल जोडने के लिए एक ट्रेंडी, कॉम्पैक्ट छाता ले जाना न भूलें।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, विदिशा ने 2007 में एसपी एंटरटेनमेंट की तेलुगु फिल्म मां इद्दारी मध्य से एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने अला, प्रेम, अथिली सत्तीबाबू एलकेजी जैसे अन्य तेलुगु प्रोजेक्ट्स में भी काम किया।

वह कन्नड़ फिल्म नलि नलियुथा का हिस्सा रहीं। तमिल फिल्मों में उन्होंने कथावरायण और मलयालम फिल्म लकी जोकर्स में भी काम किया है।

छोटे पर्दे की बात करें तो उन्होंने टीवी शो ये है मोहब्बतें से शुरुआत की थी। इसके बाद, वह मेरी गुडिया, श्रीमद् भागवत महापुराण, दुर्गा-माता की छाया और काशीबाई बाजीराव बल्लाल जैसे टीवी शो में नजर आईं।

17 अफगानी महिला क्रिकेटरों ने आईसीसी के सामने जोड़े हाथ, मांगी मदद

नई दिल्ली। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बीते कुछ सालों में काफी शानदार खेल दिखाया है। इस टीम ने विश्व स्तर पर अपने खेल से कई बड़ी टीमों को हैरान किया है। हाल ही में इस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप-2024 के सेमीफाइनल में जगह बना हर किसी को हैरान कर दिया था। अब इस देश की महिला क्रिकेटरों को आईसीसी की मदद की जरूरत है। अफगानी महिलाओं ने आईसीसी से गुहार लगाई है।

अफगानिस्तान की 17 महिला क्रिकेटरों ने आईसीसी को एक पत्र लिखा है और क्रिकेट की सवीच्च संस्था से मदद मांगी है। इन महिलाओं ने आईसीसी के सामने एक मांग रखी है ताकि वह अपनी क्रिकेट को जारी रख सकें और बेहतर भी कर सकें।

बेरिल तूफान की वजह से बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया

ब्रिजटाउन (बारबाडोस),भारतीय टीम तूफान बेरिल के कारण टी20 विश्व कप 2024 की जीत के बाद भी बारबाडोस में ही फंसी हुई है। टीम को सोमवार को यानी आज न्यूयॉर्क और फिर भारत के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम का शेड्यूल बाधित हुआ है। टीम का शेड्यूल पहले न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट, उसके बाद दुबई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट और अंत में भारत के लिए वापसी शामिल थी।

विश्व कप विजेता टीम, जिसे पहले सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे) बारबाडोस से रवाना होना था, उसे बेरिल तूफान के कारण बदलाव करना पड़ा। यह श्रेणी 3 तूफान है जो अब एक अत्यंत खतरनाक श्रेणी 4 में तब्दील हो गया है।

हालांकि, वर्तमान में यह तय नहीं है कि टीम इंडिया कब उड़ान भरेगी। तूफान के कारण वहां के एयरपोर्ट पर अभी ऑपरेशन रुके हुए हैं। स्थिति यह है कि एयरपोर्ट को एक दिन के लिए बंद करना पड़ सकता है।

बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन द्वीप, ग्रेनेडा और टोबैगो के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार, सोमवार सुबह (स्थानीय समय) विंडवार्ड द्वीप पर पहुंचने पर बेरिल के बेहद खतरनाक तूफान बने रहने की संभावना है। सोमवार तक बारबाडोस और विंडवार्ड द्वीप में 3 से 6 इंच बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने कहा है कि बेरिल के बेहद खतरनाक तूफान बने रहने की संभावना है क्योंकि इसका केंद्र विंडवार्ड द्वीप से होते हुए पूर्व कैरिबियन की ओर बढ़ रहा है।

इंडस्ट्री ने शोबिज की वास्तविक चुनौतियों से कराया परिचितः आशा नेगी

हाल ही में रिलीज हुए शो इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस आशा नेगी ने कहा कि यह सीरीज लोगों को शोबिज की वास्तविक चुनौतियों से परिचित कराती है।हिंदी फिल्म उद्योग के अंदरूनी लोगों की झलक दिखाने वाली इस सीरीज के बारे में बात करते हुए आशा ने कहा, शो इंडस्ट्री को बहुत अच्छी समीक्षाएं मिल रही हैं और खास तौर पर इंडस्ट्री के लोगों से इसे काफी सराहना मिल रही है, क्योंकि यह हर किसी से मेल खाती है।

अपने किरदार को लेकर आशा ने कहा कि लोग उनके महत्वाकांक्षी किरदार सान्या सेन से जुड़ रहे हैं। अब तक फीडबैक बहुत बढ़िया रहा है। बहुत से लोग, खास तौर पर इंडस्ट्री के लोग मेरे किरदार से जुड़ रहे हैं।टीवी शो पवित्र रिश्ता से चर्चा में आईं एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री पर्दे के पीछे के संघर्षों को उजागर करती है।उन्होंने कहा, उद्योग से बाहर के लोगों को यह शो दिखाता है कि बाहर से ग्लैमरस दिखने वाली इस इंडस्ट्री के पीछे कड़ी मेहनत और संघर्ष होता है।इस ग्लैमर में बहुत धैर्य, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष छिपा है।बारिश, लूडो, अभय और कॉलर बम जैसी हिट ओटीटी परियोजनाओं में काम करने वाली आशा ने कहा, उद्योग से बाहर के लोग असली चुनौतियों को जान रहे हैं, जबकि उद्योग में लोग हर संवाद, एपिसोड और चरित्र से जुड़ सकते हैं।टीवीएफ से अरुणाभ द्वारा निर्मित और नवजोत गुलाटी और श्रेयश पांडे द्वारा निर्देशित, इंडस्ट्री हाल ही में अमेजन मिनी टीवी पर आई है।चंकी पांडे और गगन अरोड़ा की प्रमुख भूमिकाओं वाली इंडस्ट्री एक महत्वाकांक्षी पटकथा लेखक आयुष वर्मा (गगन अरोड़ा) की कहानी बताती है, जो बॉलीवुड के जटिल रास्तों से होकर उनके सफर को दर्शाती है।

कंगना रनौत की इमरजेंसी की नई रिलीज डेट आई सामने, 6 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी फिल्म

एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी को लेकर नया अपडेट सामने आया है।

लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत अब अपने फिल्मी करियर पर भी फोकस कर रही हैं। उनकी अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कई बार रिलीज डेट टलने के बाद अब यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर रिलीज डेट की घोषणा की।

द्रविड़ के उत्तराधिकारी की घोषणा जल्द, जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस होंगे कोचः बीसीसीआई

ब्रिजटाउन, टी20 विश्व चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजरेगी। बीसीसीआई ने बताया है कि भारतीय टीम का नया कोच और टी20 में नया कप्तान कौन होगा, इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोमवार को कहा कि क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने पुरुष टीम के मुख्य कोच की भूमिका के लिए दो नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। बता दें, टी20 विश्व कप 2024 खत्म होने के साथ ही टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। मेगा-इवेंट के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने के अंत में श्रीलंका में शुरू होने वाली आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए एक नए मुख्य कोच का स्वागत करने के लिए तैयार है।

पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और पूर्व भारतीय महिला कोच डब्ल्यू.वी. रमन इस भूमिका के लिए प्रबल दावेदार हैं।

शाह इस समय कैरेबियाई देशों में भारत की टी20 विश्व कप जीत का जश्न मना रहे हैं और टीम के साथ बारबाडोस में तूफान के कारण फंसे हुए हैं।

जय शाह ने बताया कि नया कोच 27 जुलाई से टीम के साथ श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से अपने कार्यकाल की शुरुआत करेगा। वहीं जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण टीम के कोच होंगे।

टी20 विश्व कप में भारत की जीत ने आईसीसी खिताबों के 11 साल के सूखे को समाप्त कर दिया, एक ऐसी उपलब्धि जिसका श्रेय रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव और समर्पण को जाता है।

दोनों दिग्गजों ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के साथ विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की।

एक नजर

ग्रामीणों को दी नए कानून की जानकारी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : रिखणीखाल पुलिस की ओर से ग्रामीणों को एक जुलाई से भारत में लागू नए कानून की जानकारी दी गई। पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की।

रिखणीखाल थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने ग्रामीणों को कानून के बारे में बताया कि कहा कि अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए थाने आने की अवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे ही आनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत पर आनलाइन एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। कहा कि अपराध की जीरो एफआईआर दूसरे जिलों में भी करवाई की जा सकती है। जांच के दौरान शिकायत की कार्रवाई सूचना के अधिकार में भी मांग सकते हैं। गोष्ठी में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने राष्ट्रीय गान करते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी संकल्प लिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य शालिनी बलोदी, शिवलाल, अंकुर, मिनाक्षी देवी, सीमा देवी, कैलाश जोशी आदि मौजूद रहे।

पीआरडी जवानों के निधन पर जताया शोक

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने अल्मोड़ा के विनसर अभयारण्य वनाग्नि में दो पीआरडी जवानों की आकस्मिक मौत पर शोक जताया। इस दौरान संगठन जिलाध्यक्ष ललित सिंह ने कहा कि बीती 13 जून को अल्मोड़ा के विनसर अभयारण्य में जंगलों की आग बुझाते हुए दो पीआरडी जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कहा कि दुःख की इस घड़ी में उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन पीड़ित परिवार के साथ है। शोक जताने वालों में संतोष कुमार, अशोक, प्रदीप, सुरेंद्र कुमार, मुकेश नेगी, महाराज, दीपक नेगी, यशपाल सिंह, दिनेश पाल आदि शामिल थे।

जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश पर लगी रोक

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : आगामी मानसून अवधि के दौरान जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय मानसून के दौरान संभावित आपदाओं और आकस्मिक स्थितियों के कुशल प्रबंधन और नियंत्रण हेतु लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान जनपद में प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने और नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों की पूर्ण उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदेश का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता के लिए तत्पर रहें। कहा कि अति आवश्यक कार्य पड़ने पर संबंधित अधिकारी बिना अनुमति लिए मुख्यालय ना छोड़ें। कहा कि इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुले स्कूल

रुद्रप्रयाग : बीते एक महीने के ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद सोमवार से जनपद के सभी स्कूल खुल गए हैं। स्कूली बच्चों के साथ ही शिक्षक-कर्मचारी भी स्कूलों में पहुंच गए। सुबह विद्यालयों में प्रार्थना के बाद नियमित कक्षाएं शुरू हुई। विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र हित में सभी शिक्षकों से बेहतर शिक्षण कार्य में जुट जाने का आह्वान किया। बता दें कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित था जिसके चलते जून पूरे महीने में स्कूल बंद रहे। हालांकि अब भी गर्मी और उमस पड़ रही है किंतु स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को मुख्यालय सहित जनपद के सभी कस्बों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। सुबह निर्धारित समय पर स्कूल खोले गए। हालांकि पहले दिन कई विद्यालयों में छात्र कम संख्या में पहुंचे किंतु शिक्षक और स्कूल प्रशासन शैक्षणिक कार्य में जुट गया है। वहीं एक महीने की छुट्टी के बाद स्कूलों में पहुंचे छात्र-छात्राएं भी पढ़ाई में जुट गए हैं।

36 संवदेनशील स्थानों पर 34 जेसीबी तैनात

रुद्रप्रयाग : मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न सड़कों पर 34 जेसीबी तैनात कर दी है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती ने बताया कि मानसून के दृष्टिगत सभी विभागों द्वारा अपनी-अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेसियों ने फूंका प्रदेश सरकार का पुतला

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध पर जताया रोष

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : हरिद्वार में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए महिला व बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। कहा कि देवभूमि में बेटी व महिलाओं पर अत्याचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सोमवार को महानगर अध्यक्ष सुधा असवाल के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने तहसील चौक में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में भी भाजपा नेता के पुत्र द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब एक और भाजपा नेता के एक बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्याकांड में शामिल होने से भाजपा के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे की कलई खुल गई है। वर्तमान में उत्तराखंड महिला अपराधों में पहले पायदान पर पहुंच गया है। कहा कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। चेतावनी दी गई कि यदि महिला व बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन को मजबूर होगी। प्रदर्शन करने वालों में महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, प्रदेश सचिव नीलम रावत, जिला उपाध्यक्ष सुधा शर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव विमलेश नेगी, दमयंती देवी, शांति देवी, तारा देवी, प्रमिला देवी और प्रिया आदि महिलाएं शामिल रही।

कोटद्वार में प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते कांग्रेसी

भालू व गुलदार की धमक, दहशत में ग्रामीण

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : विकासखंड बीरोंखाल के ग्राम सिमड़ी-कंडूली व कांडा में गुलदार व भालू का आतंक बना हुआ है। आए दिन जंगली जानवर ग्रामीणों को गांव के समीप घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर समिति के महासचिव जगतराम जोशी ने बताया कि सिमड़ी-कंडूली व कांडा में लगातार गुलदार व भालू की धमक बढ़ रही है। जंगली जानवरों ने बीरोंखाल राजमार्ग के समीप जंगल में पहाड़ी पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। पूर्व में यह जंगली जानवर कई गोवंशों को अपना शिकार बना चुके हैं। जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। जंगली जानवरों की धमक से सबसे अधिक खतरा स्कूली बच्चों को बना हुआ है। कहा कि जंगली जानवरों से निजात के लिए वन विभाग को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। साथ ही गांव के आसपास सोलर लाइट की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।

सक्षम ने लिया दिव्यांगों के हितों का संकल्प

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) की ओर से अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान सक्षम के सदस्यों ने दिव्यांगों के हितों को लेकर कार्य करने का संकल्प लिया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संघ चालक विष्णु अग्रवाल, सक्षम के जिला संरक्षक गिरीराज सिंह रावत, बुद्धि बल्लभ ध्यानी, सत्यप्रकाश थपलियाल, संस्था के प्रांत सचिव कपिल रतूड़ी व योगंबर सिंह रावत ने दीप प्रज्जवलित कर किया। वक्ताओं कहा कि दिव्यांगता शरीर से नहीं बल्कि मन से होती है। यदि मन में कुछ करने का जुनून हो तो शरीर से दिव्यांग व्यक्ति भी सफलता की ऊंचाईयों पर पहुंच जाता है। कहा कि सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र ने अब तक 623 दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। दिव्यांगों का हित ही सक्षम का पहला कर्तव्य है। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों को छाता व शैक्षणिक सामग्री भी बांटी। इस मौके पर इकाई के सचिव विपुल उनियाल, गोविंद प्रसाद डंडरियाल, डा. सुरेंद्र लाल आर्य, दलजीत सिंह, पीएल खंतवाल, चंद्र प्रकाश नैथानी, देवानंद कुकरेती, ओजस रावत, रमा कांत कुकरेती, संदीप उनियाल, अमित सजवाण, सुदीप बैंठियाल, रूप सिंह, इंदु नौटियाल, साधना रतूड़ी, हेमा जदली, आकाश आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने आठ चालकों के डीएल किए जब्त

जयन्त प्रतिनिधि।पौड़ी : जिले की पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। पुलिस जहां शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के डीएल जब्त कर रही है, वहीं वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। रविवार को जिले की पुलिस ने आठ वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा और सभी चालकों के डीएल जब्त कर लिये है। थाना लक्ष्मणझूला ने 5, श्रीनगर ने 2, थाना लैंसडान ने 1 डीएल इस मामले में जब्त किया है। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिले में प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चालकों को इसको लेकर समझाया भी जा रहा है। अभी तक पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 106 वाहन चालकों के डीएल जब्त की कार्रवाई कर दी है। इसके साथ ही एमवी एक्ट में 129 वाहनों के चालान किए गए है। इनमें से 100 वाहनों से 62 हजार 750 रुपए का संयोजन शुल्क वसूला गया है। 29 वाहनों का चालान कोर्ट को भेजे गए हैं। एसएसपी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरूद्ध कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा।

श्रीनगर में हरेला पर्व की तैयारियां शुरू

श्रीनगर : नगर निगम सभागार में सोमवार को एसडीएम/नगर आयुक्त नुपूर वर्मा ने हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर निगम और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।

इस दौरान एसडीएम ने नगर क्षेत्र में पौध रोपण किये जाने को लेकर स्थानों को चिन्हित करने को कहा।

ग्राम प्रधानों ने की कार्यकाल बढ़ाने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने सोमवार को एक राज्य एक चुनाव की मांग के साथ ही पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने की मांग की है।

इस संबंध में एडीएम के माध्यम से सीएम को भी ज्ञापन भेजा गया। पौड़ी में सोमवार को जिले के विभिन्न ब्लाकों में ग्राम प्रधान जुटे।

इस दौरान ग्राम प्रधानों ने स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कदम नहीं उठता तो वह जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद एडीएम पौड़ी ईला गिरी के साथ ग्राम प्रधानों की बैठक भी जिला सभागार में हुई। जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

अब न्याय के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

एएसपी ने आमजन को दी नए कानून की जानकारी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने आमजन को देश में जुलाई से लागू हुए नए कानूनों की जानकारी दी। कहा कि अब पीड़ितों को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भारत को ब्रिटिश शासनकाल में लागू किए गए कानूनों से छुटकारा मिला है। इससे कही न कहीं अपराध पर भी काफी लगाम लगेगी। सोमवार को आमजन को कानूनों की जानकारी देते हुए एएसपी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों में लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही थी। लेकिन, अब नए कानूनों से लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। नए कानूनों के लागू होने पर अब इलेक्ट्रानिक मीडिया को शामिल कर दिया है। नए कानूनों में इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की बजाय भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य (अधिनयम एवीडेंस एक्ट) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) कर दिया गया है। कहा कि पहले पुराने कानूनों के तहत अपराधी पर आरोप तय करने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन, अब नए कानूनों के तहत तीस दिन के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य है। कहा कि नए कानूनों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी नए कानूनों के बारे में जानकारी मिल सके। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक जयपाल सिंह, नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रवीण भाटिया, सुभाष पांडे, मनोज पांथरी, नईम अहमद, कुलदीप रावत मौजूद रहे।

आमजन को नए कानून की जानकारी देती एएसपी जया बलूनी

व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार: प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से संबद्ध कोटद्वार नगर उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान पदाधिकारियों ने कोटद्वार को बेहतर व्यापार का शहर बनाने की योजना पर भी चर्चा की। रविवार देर शाम को नजीबाबाद रोड स्थित एक बारातघर के सभागार में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित पदाधिकरियों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने नौजवान पदाधिकरियों को चुना है। नौजवान पदाधिकारी पुराने व्यापारियों से अनुभव लेकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। दिलीप रावत ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारियों का एकजुट होना जरूरी है। व्यापारी एकजुट होंगे तो सरकार भी उनकी बात सुनेगी। इस अवसर पर राजेंद्र अंथवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, जिला महामंत्री लाजपत राय भाटिया, राकेश गर्ग, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला, मनोज पांथरी, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आकाश फूल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देते अतिथि

पशुपालकों ने की हड़ताल, डेयरी विकास को नहीं दिया दूध

रुद्रप्रयाग : डेयरी विकास विभाग की कार्यशैली से नाराज जनपद के पशुपालकों ने एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने विभाग पर आरोप लगाया कि पशुपालकों की किसी भी तरह से सुध नहीं ली जा रही है, जिससे उनके सामने कई मुश्किलें पैदा हो रही है। उन्होंने विरोध स्वरूप डेयरी विकास को दूध नहीं दिया। विभिन्न मांगों को लेकर जनपद के पशुपालन व दुग्ध व्यवसायियों ने सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल की। पशुपालक अजय कप्रवाण, राकेश बिष्ट, सुभाष भट्ट, हरीश डोभाल ने कहा कि डेयरी विभाग दुग्ध व्यवसायियों से कम दाम में दूध लेती है, जबकि सुविधाएं देने नाम पर कुछ भी नहीं है। कहा कि दो माह तक सरकार की धस्यारी योजना बंद थी। जंगलों में आग लगने से उनके सम्मुख घास का संकट पैदा हो गया था। बावजूद विभाग ने पशुपालकों की मदद करने के बजाय अपने हाथ खड़े कर दिए।

जल समाधि लेने की दी चेतावनी

नई टिहरी : टिहरी बांध प्रभावित उत्तरकाशी जिले के आंशिक डूब क्षेत्र में शामिल भल्ड गांव के ग्रामीणों ने पूर्ण विस्थापन करने की मांग को लेकर सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा कि लंबे समय बाद भी उनके विस्थापन को लेकर शासन-प्रशासन और टीएचडीसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील के जल स्तर के कारण उनके मकानों और खेतों में लगातार दरारें पड़ रही हैं। समस्या हल नहीं होने पर उन्होंने आगामी 15 जुलाई से बेमियादी धरना और झील में ही जल समाधि लेने का ऐलान किया है।

उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक का भल्ड गांव टिहरी झील के जलस्तर आरएल 835 पर स्थित है। गांव में 75 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। पूर्व में पुनर्वास विभाग ने गांव के 15 परिवारों का विस्थापन कर दिया था, लेकिन 35 परिवारों को इससे वंचित रखा गया है। पूर्व बीडीसी सदस्य कमलू लाल की अगुवाई में गांव के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या बताई। कहा कि उनके गांव का एक्सपर्ट कमेटी ने सर्वे नहीं किया। जबकि गांव में झील के कारण लगातार भू-धंसाव हो रहा है। बरसात में समस्या और विकराल हो जाती है। शासन-प्रशासन को गांव के विस्थापन की मांग को लेकर लिखित, मौखिक और धरना-प्रदर्शन से अवगत कराने के बावजूद कोई सकारात्मक कार्यवाही न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। चेतावनी दी कि यदि एक पखवाड़े के भीतर समस्या हल न हुई तो वह 15 जुलाई से धरना-प्रदर्शन और झील में ही जल समाधि लेंगे।

सूचना

मैंने अपना नाम गपुरी बेगम से बदलकर गफूरन बेगम रख लिया है। भविष्य में मुझे गफूरन बेगम पत्नी गफरूद्दीन के नाम से जाना पहचाना जाय।

ग्राम भैड़गांव, पोस्ट मोहनी संकरी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड, पिन.246149.
(2042/21)

सूचना

मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में नाम Shivansh Bhatt गलत दर्ज हो गया है। जबकि सही नाम Shivay Bhatt है।

RAJ MOHAN VILLAGE BHETI POST OFFICE ROURKHAL DISTT. PAURI GARHWAL UTTARAKHAND.
(2043/21)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति के संदीप सिंह नेगी के रिकॉर्ड में मेरा नाम सरिता दर्ज हे, जो कि गलत है। जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम सरिता नेगी पत्नी संदीप सिंह नेगी है। जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में अंकित है। अतः मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम सरिता नेगी पत्नी संदीप सिंह नेगी लिखा/पढ़ा जाय।

सरिता नेगी पत्नी संदीप सिंह नेगी निवासी ग्राम देवरामपुर, पोस्ट ऑफिस शिवराजपुर, तहसील कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(2044/21)

Name change

It is to inform all that I have changed my name from Sarita W/o Sandeep Singh Negi to Sarita Negi W/o Sandeep Singh Negi. In future I shall be known as Sarita Negi W/o Sandeep Singh Negi. Address: Vill- Devrampur, PO- Shivrajpur, Tehsil- Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal, Uttarakhand- 246146
(0241/21)

भागीरथी में पानी छोड़ने की डीएम से लगाई गुहार

नई टिहरी : जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग ने सोमवार को तहसीलदार के माध्यम से डीएम टिहरी मयूर दीक्षित को टीएचडीसी द्वारा भागीरथी का जल प्रवाह बंद किये जाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया है।

जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने बताया कि ज्ञापन से अवगत कराया है कि टीएचडीसी द्वारा जून से भागीरथी का जल प्रवाह रोका गया है। जिसकी वजह से टिहरी से देवप्रयाग तक पूरी नदी सूख गई है और कुछ गदेरों का पानी इसमें आ रहा है। टिहरी से देवप्रयाग तक कई पंपिंग योजनाओं के माध्यम से गांव तक पानी पहुंचता है। नदी में जलप्रवाह रोके जाने से गांव को पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससें गांवों में बहुत ज्यादा अव्यवस्था बनी हुई है। पालतू मवेशी भी पानी न मिलने से कठिनाई का सामना कर रहे हैं। साथ ही पानी कम होने की वजह से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मछलियों का शिकार भी किया जा रहा है। जिससे पानी जहरीला हो रहा है और महामारी का खतरा बना हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद टोडरिया ने कहा कि श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार में पानी के बिना परेशानी हो रही है। टीएचडीसी द्वारा पर्यावरण का जरा भी ध्यान न रखा जाना बहुत निराशाजनक व चिंताजनक है। जिला कांग्रस कमेटी ने टीएचडीसी से शीघ्र भागीरथी नदी के जल प्रवाह छोड़ने की मांग की है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में मंगल सिंह, नगर अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत, नीरज रावत, विनोद टोडरिया, जगदीश आर्य आदि शामिल रहे। (एजेंसी)

यूपी से लापता बुजुर्ग महिला स्वजनों को सौंपी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : घर से लापता चल रही एक बुजुर्ग महिला को पुलिस ने स्वजनों के सुपुर्द किया है। महिला बीईएल रोड में सड़क किनारे अकेले बैठी हुई थी। बुजुर्ग महिला को देख उसके स्वजनों के चेहरे खिल उठे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं ऑपरेशन स्माइल टीम को गुमशुदाओं की तलाश कर उनके परिजनों से मिलाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद की ऑपरेशन स्माइल टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बुजुर्ग महिला असहाय अवस्था में कौड़िया से आगे बीईएल रोड की तरफ सड़क किनारे अकेली बैठी है। सूचना पर ऑपरेशन स्माइल टीम द्वारा तत्काल बीईएल रोड़ पहुंचकर बुजुर्ग महिला से पूछताछ की गई तो महिला कुछ भी बताने में असमर्थ थी। महिला को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा कौड़िया स्थित पुलिस चैक पोस्ट पर लाया गया। पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग महिला से मित्रता पूर्ण माहौल में वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह नजीबाबाद में गन्ना मिल के पास रहती है। पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग महिला के परिजनों से सम्पर्क किया गया तो उनकी बेटी शबाना ने बताया कि महिला का नाम मकसूदन पत्नी स्वर्गीय साबिर, निवासी गन्ना मिल, लुकादड़ी नजीबाबाद, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश हैं। शबाना ने बताया कि मेरी माता जी बिना बताये घर से चली गई थीं। इन्हें न तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। हमारे द्वारा इनकी काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस टीम द्वारा परिजनों को कौड़िया चैक पोस्ट पर बुलाकर बुजुर्ग महिला को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक सुमनलता, कांस्टेबल सत्येंद्र लखेड़ा महिला कांस्टेबल विद्या मेहता शामिल थे।

लापता बुजुर्ग महिला को स्वजनों के सुपुर्द करती पुलिस

जल स्रोत से पाइपलाइन जोड़ने पर दी आंदोलन की चेतावनी

रुद्रप्रयाग : पेयजल निगम की ओर से तल्लानागपुर फेज-2 लिफ्ट योजना के कार्य को लेकर मदोला के ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा लिफ्ट योजना के लिए जो पाइपलाइन बिछायी जा जा रही है उसे अन्य गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए मदोला गांव के जलस्रोत से जोड़ा गया है। जबकि इसी स्रोत से पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती है। तल्लानागपुर फेज-2 लिफ्ट योजना में इन दिनों कार्यदायी संस्था द्वारा योजना से जुड़े गावों के लिए पाइप बिछाने के कार्य किया जा रहा है। जिसमें कोठगी गांव भी शामिल है। किंतु यहां संबंधित ठेकेदार द्वारा मदोला के जलस्रोत से ही पाइप जोड़ दिए गए हैं। इसका पता ग्रामीणों को तब लगा जब वे अपने जलस्रोत की सफाई के लिए गए। वहां कार्य कर रहे श्रमिकों से जब गांव वालों ने इस संबंध में पूछा तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने तुरन्त पाइप हटाने को कहा।

ग्रामीणों का कहना है कि जब इस योजना में पानी नदी से लिफ्ट होना है तो अन्य जलस्रोत से पाइप जोड़ने की क्या आवश्यकता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस लिफ्ट योजना का लाभ उनके गांव को नहीं मिलना है जबकि पाइपलाइन आदि कार्य के लिए उनकी जमीन का उपयोग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान रोशनी देवी, ज्येष्ठ प्रमुख सुभाष नेगी, पूर्व प्रधान वीरेंद्र नेगी, चंद्रमोहन नेगी, नीरज नेगी, नागेंद्र नेगी, वासुदेव नेगी, अनूप नेगी, अनिल बंगारी आदि ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि कार्यदायी संस्था द्वारा यदि एक सप्ताह के अंदर यदि पाइपलाइन अन्यत्र शिफ्ट नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा पेयजल निगम विभाग का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

युवक का अब तक नहीं लगा सुराग

श्रीनगर : कोतवाली श्रीनगर क्षेत्रांर्गत नर्सरी रोड स्थित अलकेश्वर घाट से अलकनंदा नदी में बहे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है।

बीते शनिवार को नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मी 35 वर्षीय मनोज उर्फ साहिल पुत्र श्याम सिंह गजरौला उत्तर प्रदेश निवासी अलकेश्वर घाट से अलकनंदा नदी में बह गया था। जिसके बाद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राफ्ट की मदद से खोजबीन कर रही है। श्रीनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक होशियार सिंह पंखोली ने बताया कि युवक की खोजबीन जारी है।

हर माह के प्रथम शनिवार को लगेंगे बहुदेश्यीय शिविर

रुद्रप्रयाग : जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं उनकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचे इसके लिए प्रत्येक माह प्रथम शनिवार में बहुदेश्यीय शिविर आयोजित होंगे।

इस दौरान विभागों द्वारा उनसे संबंधित संचालित योजनाओं, प्रमाण-पत्र, कार्ड आदि की जानकारी देते हुए जनता को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार तहसील ऊखीमठ के सारी में जुलाई माह के प्रथम शनिवार 6 जुलाई को बहुउद्देशीय शिविर आयोजित होगा। जबकि तहसील जखोली के चिरखटिया में माह अगस्त के पहले शनिवार 3 अगस्त को बहुउद्देशीय शिविर आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान समस्त विभागों द्वारा अपने विभाग की योजना से आम जन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित तिथियों में अपने-अपने विभाग से संबंधित स्टॉल लगाकर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। (एजेंसी)

एक नजर

बुटोला ने गांव-गांव संपर्क कर मांगे वोट

चमोली : बदरीनाथ विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है। चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रत्याशी और उनके समर्थक धूप-बरसात के बीच गांव नगरों और मतदाताओं के बीच पहुंच कर वोट की अपील करते दिख रहे हैं। सोमवार को लखपत बुटोला ने बछेर के गांधी नगर, किलौंडी, रोपा मल्ला, रोपा तल्ला, टेढ़ा खंसाल, सितोडा, सोनला, बछेर कठूड आदि गांवों में पहुंच नुक्कड़ सभा और जन सम्पर्क कर जनता से लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा और विकास के लिए वोट की अपील की। बुटोला ने जनसम्पर्क के दौरान कहा बदरीनाथ की जनता बदरीनाथ के महान मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ संकल्पित है। जिस व्यक्ति के कारण चुनाव जनता पर थोपा गया है उसे बदरीनाथ की जनता इस चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। प्रचार में उनके साथ दशोली कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोविन्द सिंह सजवाण, कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष ऊषा रावत, भीम सिंह नेगी, आनन्द सिंह पंवार आदि शामिल रहे।

चमोली जिले में 12 सड़कें बंद

चमोली : चमोली जिले में मलबा आने से सोमवार को 12 ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए बंद रही। जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार तक चमोली में 30 सड़कें बाधित हो गईं थी। इनमे 18 सड़कों पर यातायात के लिए खोल दी गई है। सोमवार तक 12 ग्रामीण सड़कें बाधित रहीं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया बाधित सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। (एजेंसी)

लोगों को नये कानूनों की जानकारी दी

चमोली : कर्णप्रयाग थाना पुलिस और प्रशासन की ओर से सोमवार को लोगों को तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी दी गई। गोष्ठी में नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रमुख प्राविधानों इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ई-एफआईआर दर्ज कराने और नए कानून में जनता के हितों तथा अपराधियों के लिए किए गए कड़े प्राविधान बताए गए। नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरी रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता के साथ नये कानूनों में शामिल नई धाराओं और सजा के प्राविधानों, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित न्याय की विस्तृत जानकारी प्रदान देकर जागरूकता पंपलेट वितरित किये गए। (एजेंसी)

जनसंवाद में पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा की शिकायतें दर्ज

रुद्रप्रयाग : मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों की कुल 15 शिकायतें दर्ज की गई। जिसमें पेयजल, सड़क, विद्युत, शिक्षा आदि शिकायतें सामने आई। 8 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्राम प्रधान पिल्लू लता देवी ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि गांव में विद्युत खंबों और झूलते विद्युत तारों से हमेशा अप्रिय घटना का अंदेशा बना रहता है जिन्हें अविलंब सही किया जाना जरूरी है।

चमेली के ग्रामीणों ने बेड़ूबगड से रूमसी भौंसाल मोटर मार्ग पर पुश्ता निर्माण कार्य में हुई लापरवाही, रतूड़ा निवासी देवी लाल ने उनके आवास के समीप सोलर लाईट न लगाने तथा वार्ड नंबर 3 निवासी मोहन सिंह नेगी ने कोटेश्वर शंकराचार्य चिकित्सालय मोटर पर लोनिवि द्वारा बनाई गई नाली के क्षतिग्रस्त होने, बांसी गांव धर्मेंद्र सिंह ने उनके बीमार पुत्र के ईलाज के लिए रेड क्रॉस सोसायटी से आर्थिक सहायता देने, डांगी गांव की आईशा और डडोली गांव के राजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की मांग की। (एजेंसी)

जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम ने सुनी समस्याएं

नई टिहरी : डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 50 शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश शिकायतें ग्राम्य विकास, बिजली, पानी और सड़क प्रतिकर से संबंधित थी। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इंद्रदेव डबराल ने चोपड़ियाल गांव लग्गा चुरेड़ गांव में जीआईसी और एलोपैथिक अस्पताल के लिए दान की गई भूमि पर बने संस्थानों में उनके माता-पिता के शिलापट्ट लगाने की मांग पर तहसीलदार और सीएमओ को समन्वय बनाकर समाधान के निर्देश दिए।

भुगतान नहीं होने पर आंदोलन करेगें ठेकेदार

नई टिहरी : नगर पालिका टिहरी के पंजीकृत ठेकेदारों ने लंबे समय बाद भी विभागीय कार्यों का भुगतान न किए जाने पर रोष जताया है। कहा कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण और पूर्व में तात्कालिक आधार पर किए गए कार्यों का भुगतान भी पालिका प्रशासन नहीं कर रहा है। जिस कारण उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। सोमवार को ठेकेदारों ने इन सभी मामलों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है।

कहा कि दो साल बीतने पर भी निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं हो पाया है। बीते मार्च माह में उनके लाइसेंसों के पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बावजूद एक जुलाई तक नवीनीकरण नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के एक दिन पूर्व निविदाएं खोली गई, लेकिन आचार संहिता खत्म होने पर भी निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी नहीं किए हैं। वीआईपी कार्यक्रम और अति आवश्यक सेवा के लिए मौखिक आधार पर ठेकेदारों ने कई निर्माण कार्य कर दिए हैं, लेकिन अब भुगतान के लिए उन्हें लटकाया जा रहा है। पालिका प्रशासन बिना दस्तावेज के भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने समस्याएं हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर शेषराव ठाकरे, धनवीर कलूड़ा, रघुवीर थलवाल, सतवेंद्र नेगी, बलवीर कोहली, रमेश सजवाण, धीरेंद्र नेगी, जयपाल चौहान, दिनेश पंवार, रोशन चौहान, जयेंद्र रावत, मनजीत राणा, वीरेंद्र नेगी, मनजीत सिंह, विनोद ममगाईं, देवेंद्र चौहान शामिल रहे। (एजेंसी)

देवभूमि कांवड यात्रा 10 अगस्त से होगी शुरू

नई टिहरी : देवभूमि कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर सोमवार को जनपद के जौनपूर ब्लाक के द्वारिकापूरी भुटगांव (लालूर) में ग्रामीणों ने बैठक आयोजित की। जिसमें कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि द्वितीय देवभूमि कांवड़ यात्रा का आयोजन भगवान शिव की आराधना के लिए किया जा रहा है। 10 अगस्त को देवभूमि कावड़ यात्रा द्वारिकापूरी से हरिद्वार के के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि विश्राम हरिद्वार में होगा। 11 अगस्त को प्रातः 4 बजे हरिद्वार से द्वारिकापूरी के लिए प्रस्थान करेगी तथा 11 अगस्त को विकासनगर में विश्राम करेगी तथा 12 अगस्त को भव्य जलाभिषेक द्वारिका पूरी में किया जाएगा। द्वितीय देवभूमि कांवड़ यात्रा में अनेकों साधु, भक्त मंडलियां सहित विभिन्न श्रद्धालु शामिल होंगे। देवभूमि कावड़ यात्रा का नेतृत्व स्वामी दर्शन भारती करेंगे।

श्रावण माह में बीकेटीसी करेगी बाबा केदार की पूजा

रुद्रप्रयाग : विश्व शांति एवं कल्याण के लिए बदरी-केदार मंदिर समिति श्रावण माह में एक घंटा स्वयं बाबा केदार की पूजा अर्चना करेगी। विशेष पूजा अर्चना के दौरान सामान्य श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बीकेटीसी के वेदपाठी, आचार्य बाबा केदार का जलाभिषेक बदरी-केदार मंदिर समिति श्रावण माह में दोपहर 2 से 3 बजे तक एक घंटा स्वयं भगवान शिव की विशेष पूजा करेगी। इस दौरान बीकेटीसी के वेदपाठी, आचार्य और अन्य कर्मी शामिल होंगे। विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए बीकेटीसी बाबा केदार का अभिषेक करेगी। इस दौरान किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के गर्भ गृह में बीकेटीसी द्वारा बिना यात्रियों को कोई परेशानी दिए इस पूजन का आयोजन किया जाएगा। बीकेटीसी के सीईओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि श्रावण माह भगवान शिव का प्रिय महीना है। बदरी-केदार मंदिर समिति नियमित रूप से देश–विदेश के तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए हर समय तत्पर है। श्रावण माह के विशेष महत्व को देखते हुए बीकेटीसी विश्व शांति और कल्याण के लिए महीने भर गर्भ गृह में प्रतिदिन एक घंटा बाबा केदार का अभिषेक पूजा करेगी। इसमें समिति के वेदपाठी और आचार्य शामिल होंगे। (एजेंसी)

चिकित्सकों की समस्याओं पर मंथन किया

नई टिहरी : स्थापना दिवस पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एसोसिएशन ने चंबा में गोष्ठी आयोजित की। जिसमें चिकित्सकों को मिलकर काम करने की जरूरत बताई गई। कहा गया कि संगठन को साथ लेकर चिकित्सकों की समस्याओं पर समय-समय पर मंथन होना चाहिए।

सीएम से की पेयजल के राजकीयकरण की मांग

देहरादून। उत्तराखंड जल संस्थान एवं पेयजल निगम संयुक्त मोर्चे ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात कर पेयजल के राजकीयकरण की मांग की। मुख्य संयोजक जितेंद्र सिंह देव के नेतृत्व में सीएम से हुई मुलाकात में कर्मचारियों ने राजकीयकरण होने तक ट्रेजरी से वेतन, पेंशन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।

सीएम आवास में हुई मुलाकात में मोर्चा पदाधिकारियों ने सीएम को मांग पत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि पेयजल के राजकीयकरण को लेकर सरकार जल्द पुराना वादा निभाए। पेयजल के राजकीयकरण और राजकीयकरण होने तक ट्रेजरी से वेतन, पेंशन भुगतान को लेकर शासन को रिपोर्ट मिल गई है। सरकार जल्द वित्त का अनुमोदन लेने के साथ ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाकर मंजूरी दिलाए। कहा कि पूर्व में वित्त विभाग इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे चुका है। कहा कि ऐसा किए जाने से सबसे बड़ा लाभ सरकार को ही होने जा रहा है। पेयजल के राजकीयकरण होने से योजनाओं के निर्माण और संचालन में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जल निगम का सेंटज का पैसा और जल संस्थान का पानी के बिलों का पैसा शासन को मिलने से कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला है। सीएम की ओर से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य संयोजक जितेंद्र देव, प्रदेश संयोजक रमेश बिंजोला, विजय खाली, अजय बेलवाल, श्याम सिंह नेगी, संदीप मल्होत्रा, लक्ष्मी नारायण भट्ट, धन सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

व्यापारी पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

चमोली : देवाल बाजार में रविवार शाम को किसी बात को लेकर दो व्यापारियों के बीच कहासुनी होने हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर उन्हे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं व्यापार संघ ने पुलिस से बाहरी व्यापारी के सत्यापन करने की मांग उठाई है।

देवाल बाजार में स्थित उत्तर प्रदेश बिजनौर थाना नगीना ग्राम सेदखेडी निवासी कमल पुत्र दिनेश और उसका भाई गौरव पर स्थानीय व्यापारी मानमती धार कुंवर पाटा निवासी मनोज कुमार पुत्र भीम सिंह और सुया गांव निवासी खुशाल सिंह पुत्र भरत सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपी नाई और उसके भाई पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। हमले में मनोज के नाक और अन्य जगह गहरे घाव हुए हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों ने की कार्यकाल बढ़ाने की मांग

नई टिहरी : त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर्स और जिला पंचायत सदस्यों ने डीएम कार्यालय पर सांकेतिक धरना देकर प्रधानमंत्री और सीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने एक प्रदेश एक पंचायत चुनाव कराने की मांग की है।

कहा कि हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल अभी दो साल अवशेष बचा है। ऐसे में पूरे प्रदेश के पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा की अगुवाई में पंचायत प्रतिनिधियों ने सीएम को भेजे ज्ञापन में बताया कि कोविड-19 के कारण उनका दो साल का कार्यकाल पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान पंचायतों की खुली बैठक तक नहीं हो पाई। ऐसे में ऐक्ट में प्रावधान है कि भयंकर दैवीय आपदा अथवा किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि कार्यकाल में व्यवधान आए तो उसे बढ़ाया जाए। कहा कि उत्तराखंड से संदेश जाना चाहिए कि एक देश एक चुनाव की दिशा में यहां एक प्रदेश एक पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक प्रमुख प्रतापनगर प्रदीप चंद रमोला, चंबा शिवानी बिष्ट, जाखणीधार सुनीता देवी, ललित सुयाल, सुधीर बहुगुणा, दिनेश भजनियाल, परमानंद मैठाणी, अनीता कोठारी, दिनेश जोशी, संगीता रावत आदि शामिल रहे। (एजेंसी)

ऋषिकेश में नाबालिग द्वारा नवजात शिशु को जन्म देने के मामले का महिला आयोग ने लिया संज्ञान

देहरादून। राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में शनिवार एक नाबालिग द्वारा नवजात शिशु के जन्म देने के मामले का राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अस्पताल पहुंचकर नवजात की उचित देखरेख व नाबालिग लड़की को आवश्यक उपचार के लिए स्वास्थकर्मियों सहित जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट को निर्देश दिए हैं। शनिवार की रोज एक नाबालिग लड़की द्वारा नवजात शिशु के जन्म देने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मामले में राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। चिकित्सालय प्रशासन से नाबालिग व नवजात के स्वास्थ्य की स्थिति के बाबत जानकारी लेने के बाद नवजात व पीड़िता की पूर्ण देखभाल व उचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने मामले में एसओ रानीपोखरी से मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए है, जिसपर एसओ ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश प्रशासन की ओर से एक सूचना भेजी गयी थी। जिसमें बताया गया कि चिकित्सालय में रानीपोखरी क्षेत्र की एक नाबालिग ने नवजात शिशु को जन्म दिया है। मामले की जांच करने के लिए महिला उप निरीक्षक को चिकित्सालय भेजा गया। इस मामले में पोक्सो अधिनियम और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आपदाओं से निपटने में उत्तराखंड का सहयोग करेंगे केंद्रीय संस्थान

देहरादून। राज्य में आपदाओं से होने वाले नुकसान की समय पर सूचना और प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ सरकार की मदद करेंगे।

सोमवार को सचिवालय में केंद्रीय संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में आपदा प्रबंध एवं पुनर्वास विभाग ने आपदा का पुर्वानुमान मॉडल तैयार करने का अनुरोध किया है। खासकर भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ के क्षेत्र पर फोकस करने का अनुरोध किया है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अनुसंधान संस्थानों के शोध और प्रयोग आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में काफी सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों से पूर्वानुमान को लेकर एक मॉडल विकसित करने को कहा। यह ऐसा मॉडल हो जिससे पता लग सके कि कितनी बारिश होने पर भूस्खलन की संभावना हो सकती है। बैठक में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के निदेशक डॉ. ओपी मिश्रा ने बताया कि रियल टाइम लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर अमृता विश्वविद्यालय ने कार्य किया है। उनके रिसर्च का लाभ उत्तराखंड में भूस्खलन की रोकथाम में उठाया जा सकता है। सचिव ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन संचालित नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी को आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का मूल्यांकन करने को कहा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े डाटा को एमईएस को भेजने के निर्देश दिए। इससे इसकी कारगरता का पता चल सकेगा। साथ ही एनआईएच रुड़की के वैज्ञानिक बाढ़ मैदान जोनिंग की रिपोर्ट और उससे संबंधित डेटा के आधार पर ठोस बाढ़ नियंत्रण योजना बनाने को कहा।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, मौसम विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सीबीआरआई रुड़की, एनजीआरआई हैदराबाद, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता तथा देहरादून आदि संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस मौके पर एसीईओ आनंद स्वरूप, राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार, मौसम केंद्र के निदेशक डॉ. विक्रम सिंह, डीडी डालाकोटी, मनीष भगत, तंद्रीला सरकार, रोहित कुमार, डॉ. पूजा राणा, वेदिका पंत, हेमंत बिष्ट, जेसिका टेरोन आदि मौजूद रहे।

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया

देहरादून। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सोमवार को मेहूवाला माफी कैंप कार्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव व जिला प्रभारी समाजवादी पार्टी देहरादून गुलफाम अली ने कहा कि अखिलेश यादव ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अगड़ी जातियों को एक सुत्र में बांधकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उत्तराखंड में सपा को मजबूत करने का संकल्प करने की बात कही। साथ ही नीम के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूहि अंजुम, जिलाध्यक्ष देहरादून सगीर मिर्जा, मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव नीरज यादव, महिला सभा मुरादाबाद की जिला अध्यक्ष अफरोज जहां वारसी, जिला प्रमुख महासचिव आरिफ वारसी, रेडक्रास देहरादून के जिला अध्यक्ष डॉ सलीम अंसारी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र कुमार नेगी, सुभाष जसौरिया, जिला सचिव पुष्कर सिंह आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री धामी ने की राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाईन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में दो दिन सुनवाई अनिवार्य किया जाए। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी कारणवश तिथि को न्यायालय में नहीं बैठ पाये तो, इसका उन्हें कोर्ट डायरी में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। उन्होंने गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिये कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के वादों को निस्तारण के सबंध में नियमित समीक्षा करें।

उन्होंने निर्देश दिये कि 'अपुणि सरकार पोर्टल' के तहत सेवा के अधिकार में जो सेवाएं दी जा रही हैं, वह लोगों को निर्धारित समयावधि में मिले, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की अधिक से अधिक सेवाएं पोर्टल से जोड़ी जाय। तहसीलों में आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को समय–समय पर तहसीलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये हैं।

अमर शहीद मेजर दुर्गामल्ल को 111 वीं जन्म जयंती पर किया नमन

देहरादून। उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति, गोखाली सुधार सभा एवं सहयोगी संस्थाओं के तत्वाधान में अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के 111 वें जन्म जयन्ती समारोह का आयोजन सोमवार को शहीद मेजर दुर्गा मल्ल योगा पार्क गढ़ी कैंट में किया गया। गोर्खाली सुधार सभा अध्यक्ष पदम सिंह थापा, उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, मेक बहादुर थापा ने शहीद मेजर दुर्गामल्ल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन, माल्यार्पण किया। इस मौके पर हुए समारोहा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मीडिया प्रभारी प्रभा शाह ने जीवन परिचय देते हुए कहा कि शहीद मेजर दुर्गा मल्ल(01 जुलाई 1913–25 अगस्त 1944) आजाद हिंद फौज के प्रथम गोर्खा सैनिक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्गा मल्ल का जन्म डोईवाला में गोर्खा राइफल्स के नायब सुबेदार गंगाराम मल्ल क्षेत्री एवं पार्वती देवी के घर में हुआ। वे 1931 में मात्र 18 वर्ष की आयु में 2/1 गोर्खा राइफल्स में भर्ती हो गये। लगभग 10 वर्ष तक सेवारत रहने के बाद 01 सितम्बर 1942 को आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। 27 मार्च 1944 को महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करते समय अंग्रेजी सेना ने मणिपुर में कोहिमा के पास पकड़ कर युद्धबंदी बना लिया। 25 अगस्त 1944 को उन्हें लालकिले में फांसी दे दी गई।

सुराज सेवा दल ने अवैध निर्माण को लेकर उठाए सवाल

देहरादून। सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता सोमवार को बस्तियों में कार्रवाई करने के मुद्दे को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे।

कार्यालय वरिष्ठ अधिकारियों के नहीं मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच किया। लेकिन पुलिस ने किशननगर चौक पर ही रोक लिया। जिन्हें पुलिस बिंदाल चौकी लाया गया। जहां से बाद में छोड़ दिया गया। जोशी ने कहा कि बस्तियों में गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन नदी नालों के किनारे जो सरकारी जमीनें कब्जाकर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही।

मुख्यमंत्री धामी ने ली उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कैलेंडर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 02 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका टाईमलाईन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई, 2026 तक पूर्ण किया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही की जाए। हरिद्वार में 05 लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवस्थापना विकास और तकनीकि दक्षता से संबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति की लिए की गई थी, उस हिसाब से कार्य किये जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

उन्होंने निर्देश दिये कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू–उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए।

उप चुनाव के लिए पोलिंग कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण शुरू

चमोली : बद्रीनाथ विधानसभा उप चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचन्द्रन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की मौजूदगी में सोमवार को पीजी कॉलेज गोपेश्वर में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 464 पोलिंग कार्मिकों को दूसरा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम व वीवीपैट का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 920 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन सोमवार को 116 पोलिंग पार्टियों के 464 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जबकि शेष 114 पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण 02 जुलाई को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने पोलिंग कार्मिकों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण को गंभीरता से पूरा करें। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को भली भांति समझे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अध्ययन करें और प्रशिक्षण के दौरान अपनी सभी शंका व संशय का समाधान कर लें। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियां निर्धारित रूट प्लान के अनुसार पोलिंग स्टेशन के लिए मूवमेंट करें। किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें। मतदेय स्थलों पर पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदान कराया जाए। फार्म-17 सी सहित सभी चुनाव प्रपत्रों को सावधानी से भरा जाए। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों से वेबकास्टिंग की जाएगी। शैडो एरिया वाले बूथों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। पीठासीन अधिकारी के अलावा किसी को भी मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदेय स्थलों पर इसका सख्ती से अनुपालन किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी कार्मिकों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी।प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि सभी मतदान कार्मिक अपने सेक्टर ऑफिसर के संपर्क में रहे और कोई भी शंका या संशय होने पर तत्काल अपने सेक्टर अधिकारी को इसकी जानकारी दे और इसका समाधान करें। मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल कराने के साथ ही चुनाव के दौरान प्रत्येक दो घंटे में पीडीएमएस के माध्यम से मैसेज भेजना सुनिश्चित करें। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश भी मौजूद थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक नोडल आनंद सिंह, मास्टर ट्रेनर प्रवक्ता एपी डिमरी, मनोज तिवारी, जयदीप झिंक्वाण, दिगपाल रावत, केसी पंत, जयवीर रावत एवं विनोद रावत ने पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों सहित जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ईवीएम का सामान्य और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इस दौरान ईवीएम मशीन की बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट को संयोजित करने, मतदान केन्द्रों तक मशीन ले जाने, मतदान के उपरान्त मशीन सील करने तथा स्ट्रांग रूम तक मशीन को सुरक्षित पहुंचाने सहित विभिन्न चुनाव प्रपत्र भरने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। (एजेंसी)

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com